# पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के मायने

drishtiias.com/hindi/printpdf/petroleum-price-hike

## पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के मायने

### संदर्भ

- पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हमेशा ही एक विवादपूर्ण विषय रहा है।
- जुलाई 2018 में पेट्रोल एवं डीज़ल की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिली जिससे मीडिया एवं देश के अन्य प्रतिष्ठानों में काफी शोरगुल देखा गया।

### चुनौतियाँ

- अपनी आवश्यकता की 83% आयात पर निर्भरता और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक होने के कारण बढ़ती कीमत एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
- ईरान से आयात को कम करने हेतु अमेरिकी दबाव भी भारत में कीमत वृद्धि का कारण हो सकता है।
- कीमतों में वृद्धि व्यापार घाटे को बढ़ाएगा, जो अंतत: चालू खाता घाटे में वृद्धि करेगा।

### कीमत वृद्धि के कारण

- पेट्रोलियम प्लानिंग एवं एनालिसिस सेल के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है।
- भारतीय बास्केट (Indian Basket) के कच्चे तेल का औसत मूल्य वर्ष 2016-17 में $47.56 प्रति बैरल था जो मार्च 2018 में $63.80 प्रति बैरल हो गया।
- उल्लेखनीय है कि कच्चे तेलों का भारतीय बास्केट ओमान, दुबई और ब्रेंट क्रूड के औसत का प्रतिनिधित्व करती है।
- तेल निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) द्वारा तेल के उत्पादन में कमी की गई है।
- बढ़ती मांग, वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध को कीमत वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

### पेट्रोलियम उत्पादों पर करारोपण

- सरकार ने वर्ष 2010 में और वर्ष 2014 में क्रमश: पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के नियंत्रण से स्वयं को मुक्त रखा है।
- 16 जून, 2017 से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत प्रतिदिन संशोधित की जाती रही है, ताकि तेज़ी से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता से उपभोक्ता को बचाया जा सके।
- जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लिये जाने तक पेट्रोलियम पदार्थ को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है।
- केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद कर आरोपित करने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर आरोपित किया जाता है।

### प्रभाव

- विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों, जैसे– परिवहन तथा पेट्रोरसायन उद्योगों के लिये कच्चा माल होने के कारण इसकी कीमतों में अस्थिरता विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन व परिवहन की कीमत को प्रभावित करती है।
- वर्तमान में रुपए के मूल्य में गिरावट के साथ तेल की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है।
- कीमतों में अत्यधिक वृद्धि व्यय को हतोत्साहित करती है जो आर्थिक संवृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- भारत कच्चे तेल की अपनी आवश्यकताओं के लगभग 83% के लिये आयात पर निर्भर है, ऐसे में तेल की कीमतों में वृद्धि भुगतान संतुलन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।

### कीमतों पर नियंत्रण

- सरकार द्वारा उत्पाद कर को कम कर।
- सड़क सेस जो कि वर्तमान में 8 रुपए प्रति लीटर है, को भी कम किया जा सकता है।
- पेट्रोल पंप कमीशन में वृद्धि को नियंत्रित कर।

### आगे की राह

- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, जैसे– एथेनॉल, मेथेनॉल, जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस आदि के माध्यम से पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करना होगा।
- जल एवं नाभिकीय स्रोतों से बिजली उत्पादन पर बल देना होगा तथा पवन एवं सौर ऊर्जा के प्रयोग को सुनिश्चित करना होगा।
- पेट्रोलियम को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिये।
- राजस्व के अन्य स्रोतों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।